DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

### Sickle cell anemia disease among tribes of Madhya Pradesh

**डा. सुमेर सिंह सोलंकी** (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, धन्यवाद। नर्मदे हर! महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन में एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपसभापति महोदय, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों के जनजातीय समाज में sickle cell रोग का बढ़ता प्रकोप हम सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है। Sickle cell रोग जनजातीय क्षेत्रों में एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। यह रोग एक आनुवांशिक बीमारी है, जिसे ठीक करना कठिन है। इस गंभीर बीमारी ने भारतवर्ष के मध्य, पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र के जनजातीय समूहों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है।

माननीय उपसभापति महोदय, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ जनजातीय समाज के लोगों की जाँच में करीब 11 लाख लोग इस गंभीर बीमारी से ग्रसित पाए गये, जिसमें महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति बहुत चिंताजनक है।

मैं, सदन का ध्यान मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़वानी-खरगोन, धार, अलीराजपुर एवं झाबुआ सहित मध्य प्रदेश के अनेक आदिवासी बाहुल्य जिलों का ज़िक्र करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूँ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल 52 हजार से अधिक लोगों के sickle cell के टैस्ट किये गये, जिनमें लगभग 8,000 लोग इस रोग से ग्रसित पाए गये। मेरे जनजातीय भाइयों और बहनों की यदि जांच की जाती है तो यह आंकड़ा और भी भयावह हो सकता है क्योंकि इस बीमारी का इलाज भी बहुत महंगा है, इसलिए जनजातीय समाज के गरीब भाइयों और बहनों के लिए यह आसानी से उपलब्ध नहीं है। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस बीमारी के उपचार में सार्थक प्रयास शुरू किए हैं। इस ओर कभी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने ध्यान नहीं दिया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जनजातीय समाज की भावी पीढ़ी के जीवन को इस बीमारी से सुरक्षित करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों के अस्पतालों में sickle cell रोगियों की जांच और इलाज अत्याधुनिक तकनीक से हो, ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का निवेदन करता हूं, जय हिन्द!

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

**श्रीमती छाया वर्मा** (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

**डा. विकास महात्मे** (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषय से अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

**Need to re-visit the categorization of forests in the State of Forest Report**

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, in recent times, we have been witnessing extremely serious impacts of climate change in our country. Rightly so, India has made ambitious commitments at COP-26, at Paris. We are doing extremely well on the front of fossils-free energy. However, on creating carbon sinks to sequester 2.5 to 3 billion tones, through forests and green cover, we are extremely lagging behind. In the light of this challenge, the recently released State of Forest Report 2021 assumes great significance. We have been mentioning in a tone of great jubilation that the country's forest and tree cover has increased by 2,261 sq. km. What is worrying is that the term 'forest cover', in this report, includes monoculture crop plantations -- coffee, coconut, rubber plantation, orchards, bamboo plantation, even destructive palm plantations, plantations along roads, rails and canals, and all areas above one hectare, having canopy of more than ten per cent.

Sir, this categorization may be in line with the UNFCC. Such plantations may sequester carbon, but we cannot, by any stretch of imagination, equate them to what we understand as 'forests', where there is interplay of various life forms and have influence on soil, air, and water.

The fear is that with this kind of computation, tendency to cut down pristine forests may grow to compensate with monoculture.

Hon. Prime Minister has, time and again, said that our objective is not just to conserve forests quantitatively, but to enrich it qualitatively. We need to walk the talk. Through you, Sir, I urge that the Government makes amends in the categorization system in computation of the forest cover. Also, the data details are not in public domain. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Vandana*ji.* Your time is over. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, I urge the Government to do so. Thank you.